मुकाबले करीब 30,000 ऑर्डरों का इजाफा हुआ जबकि लैंड रोवर डिफेंडर की

में सुधार की झलक आगामी तिमाहियों में भी दिख सकती है क्योंकि हाल में कंपनी ने अपने सभी नए रेंज रोवर और रेंज रोवर स्पोर्ट्स मॉडलों के लिए बुकिंग खोली है।

सलाहकार (निर्धारित आय) जयदीप सेन ने कहा, 'परिपक्वता तक बरकरार रखने के लिए 25 फीसदी की सीमा को खत्म करने

हालांकि प्रस्ताव अभी मसौदा स्तर में हैं और अंतिम प्रारूप में कुछ पाबंदियां भी दिख सकती हैं।

हावड़ा नगर निगम

नं. 2643/ए.ई./बीएलडीजी/21-22 दिनांक- 20.12.2021

आदेश

परिसर सं.: 18/2, चक्र चंद्र मित्र लेन, वार्ड-28, आना शिबपुर, हावड़ा-711102

संबंधित सभी पक्षों को सूचित किया जाता है कि हावड़ा नगर निगम अधिनियम, 1980 के अधीन उल्लेखित संबंधित प्रावधानों तथा उसके अधीन गठित नियमों के मद्देनजर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निर्देश के अनुसार हावड़ा नगर निगम के अधीन वार्ड-28 में परिसर सं. 18/2, चक्र चंद्र मित्र लेन, आना-शिबपुर में अवस्थित भवन के अनधिकृत हिस्से को ध्वस्त कर दिया जाएगा।

इसलिए, संबंधित भवन के अनधिकृत हिस्से में निवास कर रहे हैं लोगों को ऊपर उल्लेखित परिसर को अविलम्ब खाली करने का आदेश दिया जाता है, अन्यथा खाली करने का दोबारा कोई अवसर प्रदान किए बगैर ध्वस्त करने का कार्यक्रम जारी रखा जाएगा।

संबंधित सभी पक्षों से जनहित में सहयोग करने का अनुरोध किया जाता है।

आर्डर नं. 214(2)/21-22, दिनांक: 15.1.2022

हावड़ा नगर निगम

नं. 2803/ए.ई./बीएलडीजी/21-22 दिनांक- 14.01.2022

आदेश

परिसर सं.: 27, धर्मतला रोड, थाना-मालीपांचघड़ा, हावड़ा-711106

संबंधित सभी पक्षों को सूचित किया जाता है कि हावड़ा नगर निगम अधिनियम, 1980 के अधीन उल्लेखित संबंधित प्रावधानों तथा उसके अधीन गठित नियमों के मद्देनजर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निर्देश के अनुसार हावड़ा नगर निगम के अधीन वार्ड-6 में परिसर सं. 27, धर्मतला रोड, थाना-मालीपांचघड़ा में अवस्थित भवन के अनधिकृत हिस्से को ध्वस्त कर दिया जाएगा।

इसलिए, संबंधित भवन के अनधिकृत हिस्से में निवास कर रहे हैं लोगों को ऊपर उल्लेखित परिसर को अविलम्ब खाली करने का आदेश दिया जाता है, अन्यथा खाली करने का दोबारा कोई अवसर प्रदान किए बगैर ध्वस्त करने का कार्यक्रम जारी रखा जाएगा।

संबंधित सभी पक्षों से जनहित में सहयोग करने का अनुरोध किया जाता है।

आर्डर नं. 215(2)/21-22, दिनांक: 15.1.2022

बैंक ऑफ़ इंडिया BOI Bank of India
रिश्तों की जमापूँजी

प्रधान कार्यालय: स्टार हाउस, सी - 5, "जी" ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: 66684414/36. ई-मेल: headoffice.security@bankofindia.co.in

अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई)

बैंक ऑफ़इंडिया, पूरे देश में स्थित अपनी शाखाओं / कार्यालयों में सुरक्षा गार्ड (नि: शस्त्र / सशस्त्र) प्रदान करने केलिए निजी सुरक्षा एजेंसियों (पीएसए) से तीन वर्षों की अवधि के लिए एमपैनेलमेंट हेतु 'अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई)' आमंत्रित करता है। अभिरुचि की अभिव्यक्ति दस्तावेज जमा करने के लिए अंतिम तिथि 14-02-2022 अपराह्न 01.00 बजे तक है। अधिक विवरण के लिए हमारे वेबसाइट www.bankofindia.co.in देखें। (एजीएम एवं सीएसओ)

बिज़नेस स्टैंडर्ड
कोलकाता संस्करण

बिज़नेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जॉयदीप चक्रवर्ती द्वारा सरस्वती प्रिंट फैक्टरी प्राइवेट लिमिटेड, 789, चौभागा वेस्ट, पोस्ट ऑफिस-तिलजला, कोलकाता-700105, प. बंगाल से मुद्रित एवं बिज़नेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड, C/o एपीजे बिज़नेस सेंटर, 15 पार्क स्ट्रीट, एपीजे हाउस, ब्लॉक-सी, छठा तल, कोलकाता 700016, प. बंगाल, से प्रकाशित
संपादक: कैलाश नौटियाल

आरएनआई नं0 WBHIN/2008/24333
पाठक संपादक को lettershindi@bsmail.in पर संदेश भेज सकते हैं।
टेलीफोन - 033-22101314/1022/1600 फैक्स- 033-22101599
सब्सक्रिप्शन और सर्कुलेशन के लिए कृपया संपर्क करें...
सुश्री मानसी सिंह
हेड, कस्टमर रिलेशन्स
बिज़नेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, तीसरी और चौथी मंजिल, बिल्डिंग एच, पैरागन सेंटर, सेंचुरी मिल्स के सामने, पी बी मार्ग, वर्ली, मुंबई 400 013
ई मेल.. subs_bs@bsmail.in
या 57575 पर एसएमएस करें REACHBS

डिस्क्लेमर. बिज़नेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित समाचार रिपोर्ट और फीचर लेखों के माध्यम से बाजारों, कॉर्पोरेट जगत और सरकार से जुड़ी घटनाओं की निष्पक्ष तस्वीर पेश करने का प्रयास किया जाता है। बिज़नेस स्टैंडर्ड के नियंत्रण एवं जानकारी से परे परिस्थितियों के कारण वास्तविक घटनाक्रम भिन्न हो सकते हैं। समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्टों के आधार पर पाठकों द्वारा लिए जाने वाले निवेश और लिए जाने वाले व्यावसायिक निर्णयों के लिए बिज़नेस स्टैंडर्ड कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। पाठकों से स्वयं निर्णय लेने की अपेक्षा की जाती है। बिज़नेस स्टैंडर्ड के सभी विज्ञापन सद्भाव में स्वीकार किए जाते हैं। इनके साथ बिज़नेस स्टैंडर्ड न तो जुड़ा हुआ है और न ही उनका समर्थन करता है। विज्ञापनों से संबंधित किसी भी प्रकार का दावा संबंधित विज्ञापनदाता से ही किया जाना चाहिए।
बिज़नेस स्टैंडर्ड प्रा. लि. का सर्वाधिकार सुरक्षित है। बिज़नेस स्टैंडर्ड प्रा. लि. से लिखित अनुमति लिए बगैर समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी सामग्री का किसी भी तरह प्रकाशन या प्रसारण निषिद्ध है। किसी भी व्यक्ति या वैधानिक निकाय द्वारा इस तरह का निषिद्ध एवं अनधिकृत कार्य करने पर दीवानी और फौजदारी कार्यवाही शुरू की जाएगी।

प्रति कॉपी 50 पैसे का हवाई अधिभार हर उत्तर-पूर्वी राज्य और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर लागू

प्रपत्र ए
सार्वजनिक घोषणा
(भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (निगमित व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 6 के अधीन)
मैसर्स ईसार टेक्सटाइल्स लिमिटेड के ऋणदाताओं के ध्यानार्थ हेतु

प्रासंगिक विवरण

1	निगमित कर्जदार का नाम	ईसार टेक्सटाइल्स लिमिटेड
2	निगमित कर्जदार के गठन की तिथि	13/08/1997
3	प्राधिकारी जिसके अधीन निगमित कर्जदार का गठन/पंजीकरण किया गया है	कंपनियों के रजिस्ट्रार-कोलकाता
4	निगमित कर्जदार का कॉर्पोरेट आईडेंटिफिकेशन नं./लिमिटेड लायबिलिटी आईडेंटिफिकेशन नं.	U13100WB1997PLC114506
5	निगमित कर्जदार के पंजीकृत कार्यालय तथा मुख्य कार्यालय (यदि कोई है) का पता	पंजीकृत कार्यालय: 1/433, गरियाहाट रोड, ब्लॉक-बी (चौथी मंजिल), जोधपुर पार्क, कोलकाता-700068, प.ब., भारत
6	निगमित कर्जदार के संबंध में दिवालिया आरम्भ होने की तारीख	आदेश की तारीख 14/01/2022 आईआरपी को सूचित करने की तारीख 14/01/2022
7	दिवालिया समाधान की प्रक्रिया बंद करने की अनुमानित तारीख	12.07.2022 निगमित दिवालिया समाधान की प्रक्रिया आरम्भ होने की तारीख से 180 दिन
8	अंतरिम समाधान पेशेवर के रूप में कार्यरत दिवालिया पेशेवर का नाम तथा पंजीकरण नंबर	श्री अनुप कुमार सिंह IBBI/IPA-001/IP-P00153/2017-2018/10322
9	बोर्ड के साथ यथा पंजीकृत अंतरिम समाधान पेशेवर का पता एवं ईमेल	पता: 162/8/752 लेक गार्डन्स, कोलकाता, पश्चिम बंगाल-700045 ई-मेल: anup_singh@stellarinsolvency.com
10	अंतरिम समाधान पेशेवर के साथ पत्राचार हेतु प्रयोग किया जाने वाला पता एवं ईमेल	पता: सूईट-1बी, पहली मंजिल, 22/2बी, मनोहरपुकुर रोड, देशप्रिय पार्क, कोलकाता-700029 ई-मेल: estextiles.sipl@gmail.com
11	दावा जमा करने की अंतिम तिथि	28/01/2022
12	अंतरिम समाधान पेशेवर द्वारा निर्धारित धारा 21 की उप-धारा (6ए) की अनुच्छेद (बी) के अधीन ऋणदाताओं की श्रेणियां, यदि कोई है	कर्जदारों के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार लागू नहीं
13	एक श्रेणी में ऋणदाताओं के अधिकृत प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करने हेतु चिन्हित दिवाला पेशेवरों के नाम (प्रत्येक श्रेणी हेतु तीन नाम)	कर्जदारों के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार लागू नहीं
14	(क) प्रासंगिक फार्म तथा (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण यहां उपलब्ध है	क) वेब लिंक https://www.ibbi.gov.in/home/downloads ख) पता: सूईट-1बी, पहली मंजिल, 22/2बी, मनोहरपुकुर रोड, देशप्रिय पार्क, कोलकाता-700029 ई-मेल: estextiles.sipl@gmail.com

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, कोलकाता पीठ ने दिनांक 14/01/2022 को मैसर्स ईसार टेक्सटाइल्स लिमिटेड के विरुद्ध दिवाला समाधान की प्रक्रिया आरम्भ करने का आदेश दिया है।

मैसर्स ईसार टेक्सटाइल्स लिमिटेड के ऋणदाताओं को एतद्द्वारा अंतरिम समाधान पेशेवर के पास प्रविष्टि सं. 10 में उल्लिखित पते पर दिनांक 28/01/2022 को अथवा उससे पहले अपने दावा के साथ अपने दावे जमा करने को कहा जाता है।

वित्तीय ऋणदाताओं को दावा के साथ अपने दावे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जमा करना होगा। अन्य सभी ऋणदाता दावा के साथ अपने दावे व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जमा कर सकते हैं।

प्रविष्टि सं. 12 के तहत सूचीबद्ध एक श्रेणी से संबंधित वित्तीय ऋणदाता [illegible] प्रविष्टि सं. 13 के तहत सूचीबद्ध तीन दिवालिया पेशेवरों में से अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में अपनी पसंद का उल्लेख कर सकते हैं।

दावों के गलत रहने पर अथवा झूठे साक्ष्य जमा करने पर जुर्माना लगाया जाएगा।

हस्ता/-
अनुप कुमार सिंह
अंतरिम समाधान पेशेवर

तारीख एवं स्थान: 17/01/2022, कोलकाता

मर्चेंट बैंकर तैयार करेंगे बड़े निवेशकों की सूची

पृष्ठ 1 का शेष...

- सरकारी मूल्यांकनकर्ता ने एलआईसी का अंतर्निहित मूल्य मूल्य 4 से 5 लाख करोड़ रुपये आंका है
- सरकार को एलआईसी का बाजार मूल्यांकन 15 लाख करोड़ रु. होने की उम्मीद

एक अधिकारी ने कहा कि आईपीओ का आकार काफी बड़ा होगा, इसलिए एंकर निवेशकों की ओर से व्यापक समर्थन की जरूरत होगी। हालांकि सरकार एलआईसी के पॉलिसीधारकों सहित खुदरा निवेशकों की ओर से भारी मांग की उम्मीद कर रही है। उन्होंने कहा, 'एलआईसी आईपीओ के आकार को देखते हुए एंकर निवेशकों का भरपूर सहयोग की जरूरत होगी, लेकिन खुदरा निवेशक भी बाजार की अगुआ बीमाकर्ता में निवेश करने के इच्छुक होंगे।'

सरकार द्वारा नियुक्त मूल्यांकनकर्ता ने एलआईसी का अंतर्निहित मूल्य 4 से 5 लाख करोड़ रुपये आंका है और खबरों के अनुसार सरकार बीमा कंपनी का बाजार मूल्यांकन 15 लाख करोड़ रुपये होने की उम्मीद कर रही है। एलआईसी के बाजार मूल्य का निर्धारण मर्चेंट बैंकरों से बातचीत के बाद किया जाएगा मगर 5 से 10 फीसदी हिस्सेदारी बेचने से सरकार को 75,000 से 1.5 लाख करोड़ रुपये मिल सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि एलआईसी के अंतर्निहित मूल्यांकन का काम कंपनी और अर्न्स्ट ऐंड यंग द्वारा किया गया है।

एलआईसी इस महीने बाजार नियामक सेबी के पास आईपीओ मसौदा जमा करा सकती है क्योंकि सरकार मार्च में इसका आईपीओ लाने की संभावना तलाश रही है।

एनए शाह एसोसिएट्स एलएलपी के मैनेजिंग पार्टनर संदीप शाह ने कहा, 'बड़े निवेशकों ने कई वर्षों से एलआईसी के परिचालन और परिदृश्य की समीक्षा नहीं की है, ऐसे में उन्हें कंपनी के मूल्यांकन की व्यवहार्यता पर अतिरिक्त जानकारी की जरूरत होगी।' शाह ने कहा कि कोविड महामारी की तीसरी लहर के बीच सरकार प्रमुख वैश्विक एंकर निवेशकों से संपर्क कर रही है और आईपीओ निर्गम मूल्य तथा इसके परिदृश्य की जानकारी दे रही है ताकि आईपीओ पर किसी तरह का असर न पड़े।

इस महीने की शुरुआत में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एलआईसी आईपीओ की प्रगति की जानकारी ली थी। महामारी की तीसरी लहर से कुछ अड़चन आने की आशंका के बीच सरकार को पूरा भरोसा है कि एलआईसी को मार्च में सूचीबद्ध करा लिया जाएगा।

एलआईसी के आईपीओ से मिलने वाली रकम से सरकार को चालू वित्त वर्ष के लिए तय 1.75 लाख करोड़ रुपये के विनिवेश लक्ष्य का बड़ा हिस्सा हासिल करने में मदद मिलेगी।

चौथी तिमाही में इस्पात की बिक्री बढ़ेगी

ईशिता आयान दत्त
कोलकाता, 16 जनवरी

इस्पात कंपनियां जनवरी से मार्च तिमाही के दौरान अधिक बिक्री की उम्मीद कर रही हैं। उनका मानना है कि चौथी तिमाही के दौरान वाहन श्रेणी से मांग में सुधार दिखेगा। तीसरी तिमाही के दौरान कमजोर त्योहारी मांग और आपूर्ति पक्ष की बाधाओं के कारण बिक्री की रफ्तार सुस्त रही थी।

तीसरी तिमाही के दौरान दोपहिया श्रेणी को कमजोर मांग का झटका लगा जबकि आपूर्ति संबंधी समस्याओं के कारण यात्री वाहन श्रेणी की रफ्तार को ब्रेक लग गया था। इस्पात विनिर्माताओं के अनुसार, मौजूदा रुझानों से पता चलता है कि वाहन श्रेणी से इस्पात के उठाव के संदर्भ में चौथी तिमाही बेहतर रहेगी।

आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया (एएम/एनएस इंडिया) के मुख्य विपणन अधिकारी रंजन धर ने कहा कि जनवरी से मार्च तिमाही के लिए वाहन क्षेत्र से काफी सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। उन्होंने कहा, 'ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि संभावित मांग काफी दमदार है और हमें आवंटन बढ़ाने के लिए कहा गया है।' कंपनी चौथी तिमाही के दौरान वाहन क्षेत्र से तीसरी तिमाही के मुकाबले 15 से 20 फीसदी अधिक उठाव की उम्मीद कर रही है। जेएसडब्ल्यू स्टील के निदेशक (वाणिज्यिक एवं विपणन) जयंत आचार्य ने कहा कि जनवरी से मार्च तिमाही पिछले साल की चौथी तिमाही से भी बेहतर दिख रही है। उन्होंने कहा, 'कई यात्री वाहनों के लिए प्रतीक्षा अवधि है जिससे अच्छी मांग की झलक मिलती है।'

आचार्य ने कहा, 'हम वाहन क्षेत्र से मांग में सुधार दर्ज कर रहे हैं। अक्टूबर से नवंबर के दौरान कुछ नरमी दिखी थी लेकिन दिसंबर के बाद वाणिज्यिक एवं यात्री यानी दोनों वाहन श्रेणियों से मांग में सुधार हुआ है।'

वित्त वर्ष 2022 की दूसरी तिमाही में जेएसडब्ल्यू स्टील की कुल घरेलू बिक्री में वाहन श्रेणी का योगदान करीब 19 फीसदी रहा था।

हालांकि फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि चिप की किल्लत कितनी जल्दी खत्म हो जाएगी लेकिन विश्लेषकों ने उम्मीद जताई है कि व्यवधानों में धीरे-धीरे सुधार होगा। कार के कुल वजन में इस्पात की हिस्सेदारी करीब 50 फीसदी होती है जबकि दोपहिया के मामले यह आंकड़ा थोड़ा कम है। वाहन कंपनियों की करीब 90 फीसदी इस्पात जरूरतों को टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील और एएम/एनएस इंडिया द्वारा पूरा किया जाता है। कार के लिए कुल कच्चे माल की लागत में इस्पात की हिस्सेदारी करीब 8 फीसदी होती है जबकि दोपहिया के मामले यह आंकड़ा 7 फीसदी और वाणिज्यिक वाहन के मामले 9 फीसदी है।

भारतीय कंपनी ने प्रत्यक्ष विदेशी इक्विटी पूंजी बाजार की पेशकश नहीं की है, जिससे देश के उदारीकरण के बाद से यह सबसे लंबा अंतराल पैदा हो गया है।

बाजार पर नजर रखने वाली प्राइम डेटाबेस के आंकड़ों से पता चलता है कि जुलाई 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बजट प्रस्तुति के बाद से - जब भारत ने पूंजी बाजारों के संबंध में नियमों में ढील देनी शुरू की थी, जिससे कंपनियों के लिए कारोबार करना आसान हो गया था, जिसमें प्रतिभूतियां जारी करना भी शामिल था - 30 वर्षों में विदेशी बाजारों में 31.7 अरब

भुगतान प्रदाता पाइन लैब्स अमेरिका में 50 करोड़ डॉलर की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) की योजना बना रही है। यह कंपनी सिंगापुर स्थित है, लेकिन इसके निवेशकों में भारतीय स्टेट बैंक भी शामिल है।

विदेश निर्गम इसलिए भी ध्यान दिए जाने का केंद्र रहे हैं, क्योंकि समाचारों ने इस बात का संकेत दिया है कि सरकार स्टार्टअप को सीधे विदेश में सूचीबद्ध करने की अनुमति देने के अनुरोधों पर विचार कर रही है। इस बात की संभावना नहीं है कि यह प्रस्ताव आगामी केंद्रीय बजट का हिस्सा होगा।

की थोक बिक्री सालाना आधार पर 33 फीसदी घटकर 70,000 वाहनों के दायरे में रही। जबकि इसे 16 फीसदी अधिक रहने का अनुमान जाहिर किया गया था।

थोक बिक्री में गिरावट की मुख्य वजह सेमीकंडक्टर की कमी रही। तीसरी तिमाही के दौरान खुदरा बिक्री की स्थिति कहीं अधिक खराब रही। इस दौरान खुदरा बिक्री एक साल पहले की समान अवधि में हुई बिक्री के मुकाबले 38 फीसदी घटकर करीब 80,000 वाहन रही। प्रमुख बाजारों में ब्रिटेन का प्रदर्शन सबसे खराब रहा जहां कोविड-19 के प्रभाव के कारण बिक्री में तिमाही और सालाना दोनों आधार पर भारी गिरावट दर्ज की गई। जगुआर की बिक्री में 48.7 फीसदी गिरावट से खुदरा बिक्री को झटका लगा। रेंज रोवर की बिक्री में 34.5 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। जगुआर की खुदरा बिक्री कैलेंडर वर्ष 2021 में सालाना आधार पर भी कमजोर रही। इस श्रेणी की बिक्री में कैलेंडर वर्ष 2020 के मुकाबले 15.8 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि रेंज रोवर की बिक्री में 3.4 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई लेकिन कुल बिक्री में पिछले साल 1.2 फीसदी की गिरावट आई। वैश्विक स्तर पर सेमीकंडक्टर की कमी के कारण उत्पादन प्रभावित हुआ लेकिन कंपनी ने संकेत दिया था कि चिप की आपूर्ति और थोक बिक्री में भी एक तिमाही पहले के मुकाबले सुधार हुआ है। कंपनी के लिए राहत की बात यह है कि तीसरी तिमाही के दौरान कुल ऑर्डर बुक 1,54,000 वाहनों का रहा जबकि दूसरी तिमाही में यह आंकड़ा 1,27,000 वाहनों का रहा था। नए रेंज रोवर के लिए ऑर्डर में पिछली तिमाही के मुकाबले करीब 30,000 ऑर्डरों का इजाफा हुआ जबकि लैंड रोवर डिफेंडर की

जेएलआर उत्पादों के लिए मांग में मजबूती बरकरार है और सेमीकंडक्टर की आपूर्ति को काफी सक्रियता के साथ सुचारु करने की कोशिश की जा रही है ताकि अधिक मार्जिन वाले उत्पादों का उत्पादन बढ़ाया जा सके। हालांकि थोक बिक्री विश्लेषकों के अनुमान के मुकाबले कम रही लेकिन बैंक ऑफ अमेरिका के विश्लेषकों का कहना है कि मुक्त नकद प्रवाह (एफसीएफ) के मोर्चे पर सकारात्मक उत्पाद मेल से सहारा मिला। मोतीलाल ओसवाल रिसर्च का भी कहना है कि उत्पाद मेल में सुधार होने से परिचालन संबंधी दबाव से निपटने मदद मिली।

जेएलआर तीसरी तिमाही में 15 करोड़ पाउंड के सकारात्मक एफसीएफ की उम्मीद कर रही है जबकि दूसरी तिमाही में यह आंकड़ा 66.4 करोड़ रुपये रहा था। उत्पाद मेल में सुधार की झलक आगामी तिमाहियों में भी दिख सकती है क्योंकि हाल में कंपनी ने अपने सभी नए रेंज रोवर और रेंज रोवर स्पोर्ट्स मॉडलों के लिए बुकिंग खोली है।

तरलता अनुपात (एसएलआर) को खत्म करते हुए एचटीएम श्रेणी के लिए कॉर्पोरेट बॉन्ड को अनुमति देकर दायरे को बढ़ाया गया। इसलिए बैंक अब इन बॉन्डों की कहीं अधिक खरीदारी कर सकते हैं।

इससे पहले केवल सरकार एवं राज्य सरकार की प्रतिभूतियों और कुछ बुनियादी ढांचा कंपनियों की प्रतिभूतियों को ही एचटीएम श्रेणी में रखने की अनुमति दी गई थी। इसके अलावा बैंकों को इस श्रेणी में 25 फीसदी से अधिक निवेश रखने की अनुमति नहीं दी गई थी।

फिलिप कैपिटल के सलाहकार (निर्धारित आय) जयदीप सेन ने कहा, 'परिपक्वता तक बरकरार रखने के लिए 25 फीसदी की सीमा को खत्म करने से रकम को सरकार एवं अन्य मान्यताप्राप्त प्रतिभूतियों में लगाया। हालांकि अर्थव्यवस्था में सुधार होने के साथ ही उधारी की रफ्तार भी बढ़ी है। प्रणाली में सालाना आधार पर उधारी में वृद्धि 14 जनवरी के अनुसार 9.2 फीसदी थी जबकि जमा में 10.3 फीसदी की वृद्धि हुई।

अर्थव्यवस्था के खुलने के साथ ही कंपनियां अपनी क्षमता भी बढ़ाएंगी और उसके लिए उन्हें रकम की जरूरत होगी।

विशेषज्ञों का कहना है कि बैंकों के लिए आरबीआई के मसौदा नियमों से कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार में बदलाव आएगा। हालांकि प्रस्ताव अभी मसौदा स्तर में हैं और अंतिम प्रारूप में कुछ पाबंदियां भी दिख सकती हैं।

हावड़ा नगर निगम

नं. 2643/ए.ई./बीएलडीजी/21-22 दिनांक- 20.12.2021

आदेश

परिसर सं.: 18/2, चक्र चंद्र मित्र लेन, वार्ड-28, आना शिबपुर, हावड़ा-711102

संबंधित सभी पक्षों को सूचित किया जाता है कि हावड़ा नगर निगम अधिनियम, 1980 के अधीन उल्लेखित संबंधित प्रावधानों तथा उसके अधीन गठित नियमों के मद्देनजर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निर्देश के अनुसार हावड़ा नगर निगम के अधीन वार्ड-28 में परिसर सं. 18/2, चक्र चंद्र मित्र लेन, आना-शिबपुर में अवस्थित भवन के अनधिकृत हिस्से को ध्वस्त कर दिया जाएगा।

इसलिए, संबंधित भवन के अनधिकृत हिस्से में निवास कर रहे हैं लोगों को ऊपर उल्लेखित परिसर को अविलम्ब खाली करने का आदेश दिया जाता है, अन्यथा खाली करने का दोबारा कोई अवसर प्रदान किए बगैर ध्वस्त करने का कार्यक्रम जारी रखा जाएगा।

संबंधित सभी पक्षों से जनहित में सहयोग करने का अनुरोध किया जाता है।

आर्डर नं. 214(2)/21-22, दिनांक: 15.1.2022

हावड़ा नगर निगम

नं. 2803/ए.ई./बीएलडीजी/21-22 दिनांक- 14.01.2022

आदेश

परिसर सं.: 27, धर्मतला रोड, थाना-मालीपांचघड़ा, हावड़ा-711106

संबंधित सभी पक्षों को सूचित किया जाता है कि हावड़ा नगर निगम अधिनियम, 1980 के अधीन उल्लेखित संबंधित प्रावधानों तथा उसके अधीन गठित नियमों के मद्देनजर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निर्देश के अनुसार हावड़ा नगर निगम के अधीन वार्ड-6 में परिसर सं. 27, धर्मतला रोड, थाना-मालीपांचघड़ा में अवस्थित भवन के अनधिकृत हिस्से को ध्वस्त कर दिया जाएगा।

इसलिए, संबंधित भवन के अनधिकृत हिस्से में निवास कर रहे हैं लोगों को ऊपर उल्लेखित परिसर को अविलम्ब खाली करने का आदेश दिया जाता है, अन्यथा खाली करने का दोबारा कोई अवसर प्रदान किए बगैर ध्वस्त करने का कार्यक्रम जारी रखा जाएगा।

संबंधित सभी पक्षों से जनहित में सहयोग करने का अनुरोध किया जाता है।

आर्डर नं. 215(2)/21-22, दिनांक: 15.1.2022

बैंक ऑफ़ इंडिया BOI Bank of India
रिश्तों की जमापूँजी

प्रधान कार्यालय: स्टार हाउस, सी - 5, "जी" ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: 66684414/36. ई-मेल: headoffice.security@bankofindia.co.in

अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई)

बैंक ऑफ़इंडिया, पूरे देश में स्थित अपनी शाखाओं / कार्यालयों में सुरक्षा गार्ड (नि: शस्त्र / सशस्त्र) प्रदान करने केलिए निजी सुरक्षा एजेंसियों (पीएसए) से तीन वर्षों की अवधि के लिए एमपैनेलमेंट हेतु 'अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई)' आमंत्रित करता है। अभिरुचि की अभिव्यक्ति दस्तावेज जमा करने के लिए अंतिम तिथि 14-02-2022 अपराह्न 01.00 बजे तक है। अधिक विवरण के लिए हमारे वेबसाइट www.bankofindia.co.in देखें। (एजीएम एवं सीएसओ)

बिज़नेस स्टैंडर्ड
कोलकाता संस्करण

बिज़नेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जॉयदीप चक्रवर्ती द्वारा सरस्वती प्रिंट फैक्टरी प्राइवेट लिमिटेड, 789, चौभागा वेस्ट, पोस्ट ऑफिस-तिलजला, कोलकाता-700105, प. बंगाल से मुद्रित एवं बिज़नेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड, C/o एपीजे बिज़नेस सेंटर, 15 पार्क स्ट्रीट, एपीजे हाउस, ब्लॉक-सी, छठा तल, कोलकाता 700016, प. बंगाल, से प्रकाशित
संपादक: कैलाश नौटियाल

आरएनआई नं0 WBHIN/2008/24333
पाठक संपादक को lettershindi@bsmail.in पर संदेश भेज सकते हैं।
टेलीफोन - 033-22101314/1022/1600 फैक्स- 033-22101599
सब्सक्रिप्शन और सर्कुलेशन के लिए कृपया संपर्क करें...
सुश्री मानसी सिंह
हेड, कस्टमर रिलेशन्स
बिज़नेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, तीसरी और चौथी मंजिल, बिल्डिंग एच, पैरागन सेंटर, सेंचुरी मिल्स के सामने, पी बी मार्ग, वर्ली, मुंबई 400 013
ई मेल.. subs_bs@bsmail.in
या 57575 पर एसएमएस करें REACHBS

डिस्क्लेमर. बिज़नेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित समाचार रिपोर्ट और फीचर लेखों के माध्यम से बाजारों, कॉर्पोरेट जगत और सरकार से जुड़ी घटनाओं की निष्पक्ष तस्वीर पेश करने का प्रयास किया जाता है। बिज़नेस स्टैंडर्ड के नियंत्रण एवं जानकारी से परे परिस्थितियों के कारण वास्तविक घटनाक्रम भिन्न हो सकते हैं। समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्टों के आधार पर पाठकों द्वारा लिए जाने वाले निवेश और लिए जाने वाले व्यावसायिक निर्णयों के लिए बिज़नेस स्टैंडर्ड कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। पाठकों से स्वयं निर्णय लेने की अपेक्षा की जाती है। बिज़नेस स्टैंडर्ड के सभी विज्ञापन सद्भाव में स्वीकार किए जाते हैं। इनके साथ बिज़नेस स्टैंडर्ड न तो जुड़ा हुआ है और न ही उनका समर्थन करता है। विज्ञापनों से संबंधित किसी भी प्रकार का दावा संबंधित विज्ञापनदाता से ही किया जाना चाहिए।
बिज़नेस स्टैंडर्ड प्रा. लि. का सर्वाधिकार सुरक्षित है। बिज़नेस स्टैंडर्ड प्रा. लि. से लिखित अनुमति लिए बगैर समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी सामग्री का किसी भी तरह प्रकाशन या प्रसारण निषिद्ध है। किसी भी व्यक्ति या वैधानिक निकाय द्वारा इस तरह का निषिद्ध एवं अनधिकृत कार्य करने पर दीवानी और फौजदारी कार्यवाही शुरू की जाएगी।

प्रति कॉपी 50 पैसे का हवाई अधिभार हर उत्तर-पूर्वी राज्य और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर लागू

प्रपत्र ए
सार्वजनिक घोषणा
(भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (निगमित व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 6 के अधीन)
मैसर्स ईसार टेक्सटाइल्स लिमिटेड के ऋणदाताओं के ध्यानार्थ हेतु

प्रासंगिक विवरण

1	निगमित कर्जदार का नाम	ईसार टेक्सटाइल्स लिमिटेड
2	निगमित कर्जदार के गठन की तिथि	13/08/1997
3	प्राधिकारी जिसके अधीन निगमित कर्जदार का गठन/पंजीकरण किया गया है	कंपनियों के रजिस्ट्रार-कोलकाता
4	निगमित कर्जदार का कॉर्पोरेट आईडेंटिफिकेशन नं./लिमिटेड लायबिलिटी आईडेंटिफिकेशन नं.	U13100WB1997PLC114506
5	निगमित कर्जदार के पंजीकृत कार्यालय तथा मुख्य कार्यालय (यदि कोई है) का पता	पंजीकृत कार्यालय: 1/433, गरियाहाट रोड, ब्लॉक-बी (चौथी मंजिल), जोधपुर पार्क, कोलकाता-700068, प.ब., भारत
6	निगमित कर्जदार के संबंध में दिवालिया आरम्भ होने की तारीख	आदेश की तारीख 14/01/2022 आईआरपी को सूचित करने की तारीख 14/01/2022
7	दिवालिया समाधान की प्रक्रिया बंद करने की अनुमानित तारीख	12.07.2022 निगमित दिवालिया समाधान की प्रक्रिया आरम्भ होने की तारीख से 180 दिन
8	अंतरिम समाधान पेशेवर के रूप में कार्यरत दिवालिया पेशेवर का नाम तथा पंजीकरण नंबर	श्री अनुप कुमार सिंह IBBI/IPA-001/IP-P00153/2017-2018/10322
9	बोर्ड के साथ यथा पंजीकृत अंतरिम समाधान पेशेवर का पता एवं ईमेल	पता: 162/8/752 लेक गार्डन्स, कोलकाता, पश्चिम बंगाल-700045 ई-मेल: anup_singh@stellarinsolvency.com
10	अंतरिम समाधान पेशेवर के साथ पत्राचार हेतु प्रयोग किया जाने वाला पता एवं ईमेल	पता: सूईट-1बी, पहली मंजिल, 22/2बी, मनोहरपुकुर रोड, देशप्रिय पार्क, कोलकाता-700029 ई-मेल: estextiles.sipl@gmail.com
11	दावा जमा करने की अंतिम तिथि	28/01/2022
12	अंतरिम समाधान पेशेवर द्वारा निर्धारित धारा 21 की उप-धारा (6ए) की अनुच्छेद (बी) के अधीन ऋणदाताओं की श्रेणियां, यदि कोई है	कर्जदारों के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार लागू नहीं
13	एक श्रेणी में ऋणदाताओं के अधिकृत प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करने हेतु चिन्हित दिवाला पेशेवरों के नाम (प्रत्येक श्रेणी हेतु तीन नाम)	कर्जदारों के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार लागू नहीं
14	(क) प्रासंगिक फार्म तथा (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण यहां उपलब्ध है	क) वेब लिंक https://www.ibbi.gov.in/home/downloads ख) पता: सूईट-1बी, पहली मंजिल, 22/2बी, मनोहरपुकुर रोड, देशप्रिय पार्क, कोलकाता-700029 ई-मेल: estextiles.sipl@gmail.com

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, कोलकाता पीठ ने दिनांक 14/01/2022 को मैसर्स ईसार टेक्सटाइल्स लिमिटेड के विरुद्ध दिवाला समाधान की प्रक्रिया आरम्भ करने का आदेश दिया है।

मैसर्स ईसार टेक्सटाइल्स लिमिटेड के ऋणदाताओं को एतद्द्वारा अंतरिम समाधान पेशेवर के पास प्रविष्टि सं. 10 में उल्लिखित पते पर दिनांक 28/01/2022 को अथवा उससे पहले अपने दावा के साथ अपने दावे जमा करने को कहा जाता है।

वित्तीय ऋणदाताओं को दावा के साथ अपने दावे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जमा करना होगा। अन्य सभी ऋणदाता दावा के साथ अपने दावे व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जमा कर सकते हैं।

प्रविष्टि सं. 12 के तहत सूचीबद्ध एक श्रेणी से संबंधित वित्तीय ऋणदाता [illegible] प्रविष्टि सं. 13 के तहत सूचीबद्ध तीन दिवालिया पेशेवरों में से अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में अपनी पसंद का उल्लेख कर सकते हैं।

दावों के गलत रहने पर अथवा झूठे साक्ष्य जमा करने पर जुर्माना लगाया जाएगा।

हस्ता/-
अनुप कुमार सिंह
अंतरिम समाधान पेशेवर

तारीख एवं स्थान: 17/01/2022, कोलकाता

मर्चेंट बैंकर तैयार करेंगे बड़े निवेशकों की सूची

पृष्ठ 1 का शेष...

- सरकारी मूल्यांकनकर्ता ने एलआईसी का अंतर्निहित मूल्य मूल्य 4 से 5 लाख करोड़ रुपये आंका है
- सरकार को एलआईसी का बाजार मूल्यांकन 15 लाख करोड़ रु. होने की उम्मीद

एक अधिकारी ने कहा कि आईपीओ का आकार काफी बड़ा होगा, इसलिए एंकर निवेशकों की ओर से व्यापक समर्थन की जरूरत होगी। हालांकि सरकार एलआईसी के पॉलिसीधारकों सहित खुदरा निवेशकों की ओर से भारी मांग की उम्मीद कर रही है। उन्होंने कहा, 'एलआईसी आईपीओ के आकार को देखते हुए एंकर निवेशकों का भरपूर सहयोग की जरूरत होगी, लेकिन खुदरा निवेशक भी बाजार की अगुआ बीमाकर्ता में निवेश करने के इच्छुक होंगे।'

सरकार द्वारा नियुक्त मूल्यांकनकर्ता ने एलआईसी का अंतर्निहित मूल्य 4 से 5 लाख करोड़ रुपये आंका है और खबरों के अनुसार सरकार बीमा कंपनी का बाजार मूल्यांकन 15 लाख करोड़ रुपये होने की उम्मीद कर रही है। एलआईसी के बाजार मूल्य का निर्धारण मर्चेंट बैंकरों से बातचीत के बाद किया जाएगा मगर 5 से 10 फीसदी हिस्सेदारी बेचने से सरकार को 75,000 से 1.5 लाख करोड़ रुपये मिल सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि एलआईसी के अंतर्निहित मूल्यांकन का काम कंपनी और अर्न्स्ट ऐंड यंग द्वारा किया गया है।

एलआईसी इस महीने बाजार नियामक सेबी के पास आईपीओ मसौदा जमा करा सकती है क्योंकि सरकार मार्च में इसका आईपीओ लाने की संभावना तलाश रही है।

एनए शाह एसोसिएट्स एलएलपी के मैनेजिंग पार्टनर संदीप शाह ने कहा, 'बड़े निवेशकों ने कई वर्षों से एलआईसी के परिचालन और परिदृश्य की समीक्षा नहीं की है, ऐसे में उन्हें कंपनी के मूल्यांकन की व्यवहार्यता पर अतिरिक्त जानकारी की जरूरत होगी।' शाह ने कहा कि कोविड महामारी की तीसरी लहर के बीच सरकार प्रमुख वैश्विक एंकर निवेशकों से संपर्क कर रही है और आईपीओ निर्गम मूल्य तथा इसके परिदृश्य की जानकारी दे रही है ताकि आईपीओ पर किसी तरह का असर न पड़े।

इस महीने की शुरुआत में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एलआईसी आईपीओ की प्रगति की जानकारी ली थी। महामारी की तीसरी लहर से कुछ अड़चन आने की आशंका के बीच सरकार को पूरा भरोसा है कि एलआईसी को मार्च में सूचीबद्ध करा लिया जाएगा।

एलआईसी के आईपीओ से मिलने वाली रकम से सरकार को चालू वित्त वर्ष के लिए तय 1.75 लाख करोड़ रुपये के विनिवेश लक्ष्य का बड़ा हिस्सा हासिल करने में मदद मिलेगी।

चौथी तिमाही में इस्पात की बिक्री बढ़ेगी

ईशिता आयान दत्त
कोलकाता, 16 जनवरी

इस्पात कंपनियां जनवरी से मार्च तिमाही के दौरान अधिक बिक्री की उम्मीद कर रही हैं। उनका मानना है कि चौथी तिमाही के दौरान वाहन श्रेणी से मांग में सुधार दिखेगा। तीसरी तिमाही के दौरान कमजोर त्योहारी मांग और आपूर्ति पक्ष की बाधाओं के कारण बिक्री की रफ्तार सुस्त रही थी।

तीसरी तिमाही के दौरान दोपहिया श्रेणी को कमजोर मांग का झटका लगा जबकि आपूर्ति संबंधी समस्याओं के कारण यात्री वाहन श्रेणी की रफ्तार को ब्रेक लग गया था। इस्पात विनिर्माताओं के अनुसार, मौजूदा रुझानों से पता चलता है कि वाहन श्रेणी से इस्पात के उठाव के संदर्भ में चौथी तिमाही बेहतर रहेगी।

आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया (एएम/एनएस इंडिया) के मुख्य विपणन अधिकारी रंजन धर ने कहा कि जनवरी से मार्च तिमाही के लिए वाहन क्षेत्र से काफी सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। उन्होंने कहा, 'ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि संभावित मांग काफी दमदार है और हमें आवंटन बढ़ाने के लिए कहा गया है।' कंपनी चौथी तिमाही के दौरान वाहन क्षेत्र से तीसरी तिमाही के मुकाबले 15 से 20 फीसदी अधिक उठाव की उम्मीद कर रही है। जेएसडब्ल्यू स्टील के निदेशक (वाणिज्यिक एवं विपणन) जयंत आचार्य ने कहा कि जनवरी से मार्च तिमाही पिछले साल की चौथी तिमाही से भी बेहतर दिख रही है। उन्होंने कहा, 'कई यात्री वाहनों के लिए प्रतीक्षा अवधि है जिससे अच्छी मांग की झलक मिलती है।'

आचार्य ने कहा, 'हम वाहन क्षेत्र से मांग में सुधार दर्ज कर रहे हैं। अक्टूबर से नवंबर के दौरान कुछ नरमी दिखी थी लेकिन दिसंबर के बाद वाणिज्यिक एवं यात्री यानी दोनों वाहन श्रेणियों से मांग में सुधार हुआ है।'

वित्त वर्ष 2022 की दूसरी तिमाही में जेएसडब्ल्यू स्टील की कुल घरेलू बिक्री में वाहन श्रेणी का योगदान करीब 19 फीसदी रहा था।

हालांकि फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि चिप की किल्लत कितनी जल्दी खत्म हो जाएगी लेकिन विश्लेषकों ने उम्मीद जताई है कि व्यवधानों में धीरे-धीरे सुधार होगा। कार के कुल वजन में इस्पात की हिस्सेदारी करीब 50 फीसदी होती है जबकि दोपहिया के मामले यह आंकड़ा थोड़ा कम है। वाहन कंपनियों की करीब 90 फीसदी इस्पात जरूरतों को टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील और एएम/एनएस इंडिया द्वारा पूरा किया जाता है। कार के लिए कुल कच्चे माल की लागत में इस्पात की हिस्सेदारी करीब 8 फीसदी होती है जबकि दोपहिया के मामले यह आंकड़ा 7 फीसदी और वाणिज्यिक वाहन के मामले 9 फीसदी है।